PROCESSING INDUSTRIES he pleased to suite:

(a) whether Government have made an internal decision to downgrade the importance of marine and deep-sea fisheries;

(b) whether it is a fact that there is no Joint Secretary level officer dealing exclusively with the development of deep-sea fisheries.

(c) what are the reasons for down grading deep sea fisheries; and

(d) whether any effort has been made to focus on the finding solution to the industry which is critical to Northern Andhra Pradesh?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Does not arise

(d) Schemes for setting up of cold chain, scheme on tuna and other fish processing, assistance for diversified fishing, scheme for providing interest subsidy on loan for acquisition of deep sea fishing vessels, are being implemented under the 8th Fiveyear Plan for assistance the entrepreneurs, including those from Northern Andhra Pradesh.

Marine Ecology

3878. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether the Ministry of Food Pro cessing is allowing multinational companies to come in unhindered into the fishing grounds in Bay of Bengal;

(b) what will be the fate of fishermen and small entrepreneurs based in Andhra Pradesh;

(c) whether such a move will harm marine ecology; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) No multinational company has been allowed for deep sea fishing in the Indian Exclusive Economic Zone. However, a number of Indian Companies have been permitted to set up joint venture companies in collaboration with foreign fishing companies for deep sea fishing in Indian waters by acquisition of vessels through purchase/lease. Operation of such vessels is allowed only beyond the territorial waters, which are reserved for traditional fishermen. At present, only 17 deep sea fishing vessels are in operation under Joint Venture/Lease in the Indian EEZ.

(b) to (d) Do not arise.

देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु प्राप्त हुई पेशकश

3879. श्री राम चेठमलानी: क्या खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग के एकक स्थापित करने हेतु सरकार को अगस्त, 1994 से जून, 1994 की अवधि के दौरान अनेकों पेशकश प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पेशकशों की संख्या कुल कितनी है और इनमें कुल कितना पूंजी निवेश होने की संभावना है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन एककों को शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्थापित करने का निश्चय किया गया है;

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले एककों की अलग-अलग संख्या कितनी है तथा इन एककों में अनुमानत: कितने-कितने स्थानीय लोगों को एकक-वार रोजगार प्राप्त को होने की संभावना है; और

(ङ) देश में विभिन्न राज्यों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले इन प्रस्तावित एककों की अलग-अलग संख्या कितनी है और मार्च, 1994 तक कुल कितने एकक स्थापित किए जा चुके हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई): (क) से (ङ) अगस्त 1991 से जून 1994 तक सरकार को 34,469 करोड़ रु. के प्रस्तावित निवेश वाले 2680 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिनमें 4.82 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार देने का प्रस्ताव है। सरकार ने लगभग 7060 करोड़ रु. के निवेश वाले विदेशी/अनिवासी भारतीय निवेश, निर्यातोन्मुखी यूनिटों और औद्योगिक लाइसेंस संबंधी परियोजना प्रस्तावों